



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2002/ज्येष्ठ 15, 1924

No. 144]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2002/JYAISTHA 15, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

प्रारम्भिक जाँच—परिणाम

विषय : यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस (पी एच पी जी बेस) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच।

सं. 14/6/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है —

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग की ओर से मै. दौराला आर्गेनिक्स लि., दौराला मेरठ, उत्तर प्रदेश से लिखित याचिका प्राप्त हुई जिसमें यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस जिसे पीएचपीजी बेस के नाम से भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है;
- (ii) प्राधिकारी ने उक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पाटन संबंधी आवेदन के प्राप्त होने की सूचना भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमण्डल को दी;
- (iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय शीर्ष सं. 2942 के अंतर्गत आने वाले डी (-) पैरा हाईड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच आरम्भ करते हुए दिनांक 8 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की;
- (iv) प्राधिकारी ने ज्ञात निर्यातकों, आयातकों उद्योग एसोसिएशनों तथा शिकायतकर्ता को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया;
- (v) प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियम 6 के उपनियम (3) के अनुसार याचिका की एक प्रति यूरोपीय संघ के सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत स्थित यूरोपीय आयोग शिष्टमंडल को भेजी;

- (vi) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :—
- मै० रिकोरदाती, इटली
 - मै० डीएसएम डेरेटिल एसए स्पेन दोनों निर्यातकों से उत्तर प्राप्त हुए हैं ।
- (vii) नई दिल्ली स्थित यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल को भी जांच आरंभ होने की सूचना दी गई थी और उनसे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भर कर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था;
- (viii) संबंध वस्तु के निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी :—
- मै० अरबिन्दों फार्मा लि०, हैदराबाद
 - मै० लूपिन लेबोरेटरीज लि०, मुम्बई
 - मै० कोपरान ड्रग्स लि०, रायगढ़
 - मै० सूर्या फार्मास्यूटीकल लि०, चंडीगढ़
 - मै० टोरेंट गुजरात बायोटेक लि०, अहमदाबाद
 - मै० रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि०, नई दिल्ली
 - मै० टिनी फार्मा लि०, मुम्बई
 - मै० टोरेंट गुजरात बायोटेक लि० से उत्तर प्राप्त हुआ है जिनके अनुरोधों का उल्लेख आयातकों के उत्तर में किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य उपयोक्ता/आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- (ix) याचिकाकर्ता से क्षति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिसे प्रस्तुत कर दिया गया था;
- (x) प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध रखे और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा;
- (xi) यह चिह्न इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत वैसी ही मानी गई सूचना का द्योतक है;
- (xii) इस जांच में 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 तक की अवधि शामिल है;
- (xiii) जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां फिक्की, सीआईआई, एसोचैम आदि को व्यापक प्रचालन के लिए भेजी गई थी।

ख. याचिकाकर्ता के विचार

3. याचिकाकर्ता मै० दौराला आर्गेनिक्स लि० ने अपने अनुरोधों में निम्नलिखित बिन्दु उठाए हैं :—
- (i) वर्तमान याचिका में विचारधीन उत्पाद डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस (पीएचपीजी बेस) है। इस उत्पाद को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है—
- डी (-) अल्फा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन
 डी (-) अल्फा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस
 डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन
 पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन
 डी (-) पी-हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस
 डी (-) पी-हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन, आदि
- (ii) भारत में संबंध वस्तु का आयात किया जाता है, जिसे बाद में विभिन्न आयातकों/निर्माताओं द्वारा स्वस्थाने पीएचपीजी डेन साल्ट (पीएचपीजीडीएस) में परिवर्तित किया जाता है और इस यौगिक को आगे एमोक्सिलिन तथा सेफाड्रोक्सिल के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है।
- (iii) संबंध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय-29 के उपशीर्ष संख्या 294200 तथा 29420029 के तहत 8 अंकीय आईटीसी कोड के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबंध वस्तु तथा संबंध देश/क्षेत्र से आयातित संबंध वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है, जिनका कीमत उपयोग, गुणवत्ता आदि का कोई प्रभाव पड़ सकता है। दौराला आर्गेनिक्स द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंध देश/क्षेत्र से आयातित उत्पाद में समान विशेषताएं हैं और इसलिए दोनों को समान वस्तु माना जाना चाहिए।
- (iv) याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भारत में वह संबंध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और इसलिए वह स्थिति संबंधी मापदण्डों को पूरा करता है।

- (v) इस याचिका से पहले, घरेलू उद्योग चीन जनगणना तथा सिंगापुर से पीएचपीजी के पाटन के कारण क्षति उठा रहा था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 31-12-2001 की 51/1/2001-डीजीएडी के तहत संबद्ध सामग्री पर प्रारंभिक जाँच परिणाम पहले ही जारी कर दिये थे तथा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 18/2002-सीमाशुल्क दिनांक 15 फरवरी, 2002 के तहत शुल्क 15 फरवरी, 2002 से लागू हो गया था। इसी बीच संबद्ध देश/क्षेत्र के उत्पादक/निर्यातक भी भारतीय बाजार में संबद्ध सामग्री के पाटन में इन देशों के साथ हो गए। यूरोपीय संघ से आयात बहुत कम कीमत पर शुरू हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप पाटन हो रहा है और आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- (vi) इटली और स्पेन यूरोपीय संघ के सदस्य हैं और यूरोपीय संघ में कोई सीमाशुल्क परिसीमा नहीं है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लागू करना तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक इसे पूरे यूरोपीय संघ के विरुद्ध लागू न किया जाए।
- (vii) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- (viii) याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश/क्षेत्र से निर्यातों में समग्र रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो आयात संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट है। माह-वार आयात संबंधी आंकड़े ये दर्शाते हैं कि इटली (ईयू) के निर्यातक मितम्बर, 2001 के बाद से कीमतों को तेजी से घटा रहे हैं, जो उनकी राय में अपनी परिवर्ती लागतों को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निर्यातक का एकमात्र लक्ष्य घरेलू उद्योग को उसके आरंभिक स्थिति में ही समाप्त करना है।
- (ix) याचिकाकर्ता इस क्षेत्र में नया प्रवेशकर्ता है तथा संबद्ध देश/क्षेत्र से हो रहे पाटन का उद्देश्य इस उद्योग को शुरुआती दौर में ही समाप्त करना है।
- (x) वर्तमान याचिका उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा के विरुद्ध दायर की गई है। चूंकि याचिकाकर्ता भारतीय बाजार में अपने वाणिज्यिक उत्पादन को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और संबद्ध देश/क्षेत्र से होने वाले आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन के वाणिज्यिकरण पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए आयात उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा पैदा कर रहे हैं। यद्यपि “नव स्थापित उद्योग अर्थात् मै० डीओएल ने हाल ही में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है तथापि उद्योग अभी भी बाजार में अपना स्थान नहीं बना पाया है। घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने और बाजार में अपना स्थान बनाने में अक्षम रहा है। इसके अलावा उत्पादन की आरंभिक स्थिति में इसे संबद्ध देश/क्षेत्र से हो रहे निर्यातों से वास्तविक क्षति का खतरा बना हुआ है”।
- (xi) याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विश्व में अन्य उत्पादकों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही प्रौद्योगिकी से तुलनीय है। व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहारों विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निर्यादन या उत्पादकता जैसे कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- (xii) पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के आयातों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण न केवल घरेलू उद्योग को अपनी सामान्य बिक्री कीमत प्राप्त करने से वंचित किया गया है बल्कि घरेलू उद्योग को बाजार में बने रहने में भी बाधा पहुंचाई। याचिकाकर्ता यह समझते हैं कि यूरोपीय संघ के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य पर्याप्त क्षमता है जिसमें किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार को पर्याप्त रूप से बढ़े हुए पाटित आयात होने की संभावना का पता चलता है।
- (xiii) घरेलू उद्योग ही बढ़ती हुई माँग के होते हुए भी आरंभिक स्थिति में भारी घाटा उठाया है। संबद्ध देशों से हो रहा पाटित आयात ही घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा का एकमात्र कारण है। इसके अलावा उत्पादन की आरंभिक स्थिति में घरेलू उद्योग संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर हो रहे निर्यातों द्वारा वास्तविक क्षति होने का खतरा बना हुआ है।
- (xiv) यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध देश के विरुद्ध भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए।
- (xv) इस बारे में धारा 9क(3) के तहत पाटनरोधी उपबंध निम्नानुसार है:—

“जाँचाधीन पाटित वस्तु के बारे में यदि केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि—

पाटन काफी पहले से किया जा रहा है जिससे क्षति हुई है अथवा यह कि आयातक को इस बात की जानकारी थी अथवा जानकारी होनी चाहिए कि निर्यातक पाटन कर रहा है और यह कि ऐसे पाटन से क्षति होगी; और उक्त क्षति अपेक्षाकृत ऐसे कम समय में किसी आयातित वस्तु के भारी पाटन के कारण हुई है जिससे पाटित की गई आयातित वस्तुओं के समय तथा मात्रा एवं अन्य परिस्थितियों के मद्दे नजर लगाए जाने योग्य पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव में भारी कमी आने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा (2) के तहत पाटनरोधी शुल्क लगाने की तारीख से पूर्व की किसी तारीख से परन्तु जो उपधारा के तहत अधिसूचना की तारीख से 90 दिन से अधिक नहीं होगी और भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगा सकता है और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसा शुल्क ऐसी दर से और ऐसी तारीख से संदेय होगा, जैसाकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है; यदि—

- (क) यदि पाटन काफी पहले से किया जा रहा है जिससे क्षति हुई है,
- (ख) आयातक को जानकारी थी अथवा जानकारी होनी चाहिए कि निर्यातक पाटन कर रहा है और ऐसे पाटन से क्षति होगी;

- (ग) उक्त क्षति अपेक्षाकृत ऐसे कम समय में किसी आयातित वस्तु के भारी पाटन के कारण हुई है जो पाटित की गई आयातित वस्तु के समय तथा मात्रा और अन्य परिस्थितियों के मद्दे नजर लगाए जाने योग्य पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव में भारी कमी आने की संभावना है;
- (घ) मौजूदा मामला काफी पहले के किए जा रहे पाटन का एक स्पष्ट मामला है। इससे पूर्व घरेलू उद्योग को चीन तथा सिंगापुर से सम्बद्ध सामग्री के पाटन से क्षति पहुँची है। निर्दिष्ट प्राधिकारी विस्तृत जांच कर रहे हैं और उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणामों की सिफारिश कर दी है और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनंतिम पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लगाया जा चुका है। अब सम्बद्ध देश/क्षेत्र के उत्पादक/निर्यातक सम्बद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं। इस मामले में आयातक इस बात को भलीभाँति जानते हैं कि जिस कीमत पर सम्बद्ध देश/क्षेत्र से सम्बद्ध सामग्री का निर्यात किया जा रहा है वह पाटित कीमत है क्योंकि यह कीमत पूर्ववर्ती जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संदर्भ कीमत से काफी कम है (जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रही है)
- (ङ) सम्बद्ध देश/क्षेत्र के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा कम अवधि में क्षति पहुँचाई जा रही है। पहले सम्बद्ध देश से कम आयात अथवा शून्य आयात हुए थे। पाटन शुरू हुआ और हाल ही में (विशेष रूप से सितम्बर 2001 से) उसमें तेजी लाई गई है। यह समझा जाता है कि निर्यातकों ने बड़ी मात्रा में आर्डर बुक किए हैं जिनका निर्यात किया जा रहा है;
- (च) जो कम्पनियाँ सम्बद्ध देशों/क्षेत्रों से आयात कर रही हैं, उनमें से अधिकांश कम्पनियाँ वे कम्पनियाँ हैं, जो पहले चीन तथा सिंगापुर से आयात कर थीं।

ग. निर्यातकों, आयातकों तथा उपयोक्ताओं के विचार

प्राधिकारी ने धारा 9क (i) के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजन से सम्बद्ध देश/क्षेत्र के सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भेजीं। निर्यातकों द्वारा दायर किए गए उत्तर निम्नानुसार हैं:—

क. मै. डीएसएम डेरिटिल, एसए, स्पेन

यह देखा गया है कि निर्यातक मै. डीएसएम डेरिटिल, एसए, स्पेन ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने अनुरोध में कोई भी तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि उन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिया है जो उन्हें याचिका की अगोपनीय प्रति के साथ भेजी गई थी और उन्होंने प्रश्नावली में उल्लिखित भिन्न-भिन्न परिशिष्टों के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि —

- (i) डीएसएम डेरिटिल एसए कोलेजीओ नेशनल ऑफ बारसीलोना द्वारा स्पेन के कानूनों के अनुसार स्थापित तथा पंजीकृत स्वायत्त सोसाइटी के स्वरूप का एक संगठन है।
- (ii) निर्यातक ने अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें निर्यात बिक्रियों पर उनकी सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी स्पेन या यूरोपीय संघ (घरेलू बाजार) में कोई बिक्री नहीं होती है। तथापि उन्होंने आगे यह कहा है कि उन्होंने बिक्रियाँ तीसरे देशों को की हैं।
- (iii) उन्होंने कहा कि प्रश्नावली में दिए गए उत्पादन लागत संबंधी आंकड़ों तथा उनकी लेखाकरण प्रणाली का उपयोग करके सामान्यतः निर्धारित की गई लागतों के बीच कोई अंतर नहीं है।
- (iv) निर्यातक ने कहा कि मै. डीएसएम डेरिटिल एस द्वारा भारत तथा अन्य देशों को की गई बिक्रियों पर बेची गई मात्राओं, बिक्री या व्यापार की शर्तों अथवा अन्य कारकों के वजह से लाभ के स्तरों में हुए वास्तविक परिवर्तनों का कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है।

ख. रिकार्डार्टी, इटली

- (i) मै. रिकार्डार्टी, इटली ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि वे पिछले 20 वर्षों से एलजाइम रूट (याचिकाकर्ता का रूट रासायनिक है) के द्वारा पीएचपीजी का उत्पादन कर रहे हैं और विश्व बाजार की कीमत के अनुरूप औसत कीमत पर भारतीय बाजार में इसकी पुनः बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जिस कीमत पर वे भारत में अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं, वह ठोस वार्ताओं के बाद तय की जाती है जहाँ अमोक्सी और पेन-जी की प्रति आर्डर मात्रा तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखा जाता है।
- (ii) उन्होंने कहा कि पीएचपीजी तथा डेन्साल्ट दोनों की कीमतों का ह्रास इन वस्तुओं के चीन के अनेक नए उत्पादकों द्वारा बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास पाटन संबंधी कार्रवाई के लिए संसाधन ही नहीं हैं और न ही याचिकाकर्ता के हित के विरुद्ध काम करने की कोई मंशा है।

आयातक तथा उपयोक्ता

8. केवल एक उपयोक्ता नामतः मै. टॉरेंट गुजरात बायोटेक लि: (टीजीबीएल) ने इस याचिका का उत्तर दिया है। उनके अनुरोध निम्नानुसार हैं:—

- (क) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग की अधिकतम उत्पादन क्षमता 2200—2500 मी. टन प्रति वर्ष की अनुमानित मांग की तुलना में केवल 300 मी. टन है। यूरोपिय संघ से आयातित पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क को निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है।

- (ख) उपलब्ध स्वदेशी सामग्री की गुणवत्ता उसके विनिर्देशनों को पूरा नहीं करती है जिससे उनका अपेक्षित उत्पादन नहीं होता है जिससे तैयार उत्पाद की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रभावित होती है।
- (ग) 11 यूएस डालर प्रति किग्रा. की विद्यमान कीमत पर पीएचपीजी बेस की पहुंच कीमत 870.50 रुपए प्रति किग्रा. बैठती है। जिसमें शुल्क भाड़ा निकासी प्रभार शामिल हैं जो स्थानीय विनिर्माता मै. दौराला आर्गेनिक्स लि. की विद्यमान कीमत के निकट है। इससे संकेत मिलता है कि आयात कीमत स्वदेशी कीमतों के समान है।
- (घ) मै. डीओएल लि. भारत में इसका एकमात्र उत्पादक है और सम्बद्ध सामग्री पर पाटनरोधी शुल्क लगाना एकाधिकार व्यापार बन जाएगा जो एमआरटीपी अधिनियम के विरुद्ध है।

मै. टीजीबीटी ने आयातक की प्रश्नावली का उत्तर दिया है और अनुबंध 1 से vii के अनुसार सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने अपनी कम्पनी की वर्ष 2000-2001 तथा 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच तथा जांच परिणाम

9. याचिकाकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष दायर किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और इन जांच परिणामों को निकालते समय जहां उचित पाया गया है, इसके बाद उन पर विचार कर कार्रवाई की गई है।

ङ विचाराधीन उत्पाद तथा समानवस्तु

10. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पीएचपीजी बेस (पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस) है। भारत में सम्बद्ध वस्तु का आयात किया जाता है जिसे बाद में स्वस्थाने पीएचपीजी डेन साल्ट (पीएचपीजीडीएस) में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि पीएचपीजी का प्रयोग सीधे ही अमोक्सीलीन आदि के उत्पादन में नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन या तो पीएचपीजी/पीएचपीजीडीएस के विनिर्माताओं की ओर से अथवा प्रयोक्ता अर्थात् अमोक्सीलीन आदि के उत्पादकों की ओर किया जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष 2942.00 के तहत वर्गीकरण योग्य है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार पीएचपीजी को अध्याय-29 अर्थात् 2942.0029 के तहत "अन्य श्रेणियों" में किया जाता है। वर्तमान जांच उस वर्गीकरण पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के खिलाफ है जिसके तहत उसका आयात किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. पाटनरोधी नियम के नियम 2(घ) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि समानवस्तु एक ऐसी वस्तु है जो हर तरह से जांचाधीन उत्पाद के समान या समनुरूप है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में कोई दूसरी वस्तु जिसमें जांच के अधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं।

12. याचिकाकर्ता ने दावा दिया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु हैं। विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की परिभाषा के बारे में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस की विशेषताएं सम्बद्ध देश से आयातित पीएचपीजी बेस की विशेषताओं के समान हैं। उपरोक्त के मद्दे नजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस तथा सम्बद्ध देशों से आयात किए जा रहे पीएचपीजी बेस क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजन से नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं।

न्यूनतम सीमाएं

13. याचिकाकर्ता ने यह अभ्यावेदन दिया है कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में दर्शाए गए आंकड़े प्रतिनिधिक नहीं हैं क्योंकि श्रेणी "अन्य" के तहत अन्य कार्बनिक मिश्रणों की निकासी भी उसी शीर्ष 294200 के तहत की जाती है। चूंकि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में पीएचपीजी बेस के आयात संबंधी सही आंकड़े नहीं दिए गए हैं इसलिए याचिकाकर्ता ने (गौण स्रोत अर्थात् इंटरनेशनल बिजनैस इन्फार्मेशन सर्विमिज मुम्बई (आईबीआईएस) के आंकड़ों पर विश्वास किया है। अभिकरण द्वारा दिए गए आंकड़े सीमाशुल्क दैनिक सूचियों पर आधारित हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीएचपीजी बेस को सीमाशुल्क टैरिफ के अनुसार "अन्य श्रेणी" में वर्गीकृत किया जाता है अतः डीजीसीआई एंड एस आंकड़े इन परिस्थितियों में विश्वसनीय नहीं हो सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए आईबीआईएस के आयात संबंधी आंकड़ों और जांच की अवधि के लिए माहवार आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि जांच की अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से हुए आयात न्यूनतम सीमा से अधिक रहे हैं।

च. घरेलू उद्योग

14. यह याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै. दौराला आर्गेनिक्स लिमिटेड, दौराला मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा दायर की गई है। याचिका भारत में पीएचपीजी का एकमात्र उत्पादक है। तदनुसार याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मानदंड को पूरा करता है। प्राधिकारी ने भी इस याचिकाकर्ता को उपरोक्त नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की जांच

15. धारा 9क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या

- (ii) जहाँ निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो :—
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु के उपाधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहाँ वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश से उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

मैं डीएसएम डेरेंटिल, एसए स्पेन

सामान्य मूल्य

16. मैं, डीएसएम डेरेंटिल ने उत्तर दिया है कि उनकी कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है। अपनी प्रश्नावली के उत्तर में उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में सूचना दी है। परिशिष्ट-1 के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया है कि उनकी कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी यूरोपीय संघ में इस उत्पाद की कोई बिक्रिया नहीं हुई है। परिशिष्ट-3 के अनुसार उन्होंने अन्य देशों और भारत को की गई अपनी बिक्रियों के लेखे दिए हैं, जिसे आगे बिक्रियों के महावार ब्यौरे में अलग-अलग कर दिया गया। परिशिष्ट-4 और 6 में उन्होंने भारत और अन्य देशों को की गई बिक्रियों के लिए कीमत ढांचे और बिक्री व्यवस्था के बारे में बताया है। तथापि उन्होंने प्रश्नावली परिशिष्ट 7 में आंशिक और अपूर्ण सूचना दी है। अन्य उत्पादों की मात्रा और मूल्य के संबंध में सूचना नहीं दी गई है। परिशिष्ट 8 और 10 के अनुसार उन्होंने वित्तीय और ब्याज लागतों के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी है यद्यपि इस परिशिष्ट के अनुबंध में उन्होंने पूँजी की लागत के संबंध में कुल लागत गणना प्रस्तुत की है। उन्होंने गत तीन वर्षों के लिए अपने निगमित तुलन पत्र भी प्रस्तुत किए हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि फर्म ने अन्य देशों और भारत को किए गए निर्यातों के लिए बिक्री कीमत ढांचे के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है यद्यपि वित्त और ब्याज लागतों के बारे में पूरी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और कंपनी के अन्य उत्पाद और उनके मूल्यों के बारे में दिए गए ब्यौरे अपूर्ण हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातक ने तीसरे देश के बिक्रियों संबंधी सौदेवार ब्यौरे अपूर्ण हैं। यद्यपि उन्होंने तीसरे देश में बिक्रियों संबंधी माहवार ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते हैं कि उनकी बिक्रियां व्यापार के सामान्य क्रम में हैं। जब तक किए ऐसे किसी दावे के साथ प्रश्नावली में यथापेक्षित पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है तब तक निर्यातक के उत्तरों की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रश्नावली के अनुसार समान सूचना न देकर प्राधिकारी निर्यातक के अनुरोधों का पूरी तरह स्वीकार करने से वंचित रहता है। तथापि चूंकि उन्होंने अन्य देशों के लिए किए गए निर्यातों के बारे में पर्याप्त सूचना परिशिष्ट-3 और 6 के अनुसार दी है इसलिए प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए ही सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए निर्यातकों के उत्तर को ही स्वीकार करते हैं जो आगे जांच और सत्यापन के अधीन है। प्राधिकारी ने स्वदेशी भाड़े, बीमा, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा के कारण समायोजन करने के पश्चात् तीसरे देश (प्रतिनिधिक एवं उचित तीसरे देश के रूप में) की बिक्री कीमत को ध्यान में रखने के पश्चात् सामान्य मूल्य का निर्धारण यू एस डालर में किया है।

निर्यात कीमत

17. निर्यातक ने भारत को यूएस डालर के कुल मूल्य के किग्रा. पीएचपीजी का निर्यात किया है। तदनुसार जांच की अवधि के दौरान पीएचपीजी की औसत निर्यात कीमत यूएस डालर प्रति किग्रा. बनती है। निर्यातक ने भारत के लिए कारखानागत निर्यात कीमत पर पहुँचने के लिए छूट, स्वदेशी भाड़े, बीमा, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा इत्यादि के कारण समायोजनों का दावा किया है। तथापि यह देखा गया है निर्यातक ने उपयुक्त तीसरे देश को किये गए निर्यातों की तुलना में भारत को किए गए निर्यातों के लिए कम भाड़े का दावा किया है जो कि यूरोपीय संघ के निकट है। प्राधिकारी ने भारत को किए गए निर्यातों के मामले में ईरान को किए गए निर्यातों के समान भाड़े को ध्यान में रखकर ही समायोजन किए हैं और इसी पर विचार करने के पश्चात् भारत को निर्यात बिक्री की कारखाना-गत कीमत, स्वदेशी भाड़े, बीमा, विदेशी भाड़े, विदेशी बीमा के कारण समायोजन, जो कि आगे सत्यापन/जांच के अधीन है, करने के पश्चात् यू एस डालर/किग्रा. बनती है। प्राधिकारी ने भारत के लिए कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समायोजनो एक भाग के रूप में निर्यात कीमत के 0.00 % की दर पर कमीशन को भी ध्यान में रखा है।

स्पेन के मैं, डीएसएम डेरेंटिल एसए के मामले में प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन 0.00 रुपये प्रति किग्रा. अथवा निर्यात कीमत का 6.68% निर्धारित किया गया है।

मैं, रिकोर्डेट्री इटली

18. मैं, रिकोर्डेट्री इटली ने अपने अनुरोधों को सामान्य रूप में प्रस्तुत किया है और उन्होंने केवल अपने द्वारा और याचिकाकर्ता द्वारा उपयोग की गई प्रौद्योगिकी के बारे में टिप्पणी की है। उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है इसलिए प्राधिकारी ने नियम 6(8) अर्थात् सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कार्यवाई की है और रिकोर्डेट्री के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार है। जहाँ तक निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है घरेलू उद्योग ने

जांच अवधि के दौरान इटली से कुल लदान तथा उन लदानों की वास्तविक सीआईएफ कीमतों को ध्यान में रखने के बाद निर्यात कीमत को औसत निर्यात कीमत के रूप में परिकलित किए जाने की मांग की है। प्राधिकारी ने स्वदेशी भाड़े, बीमा, विदेशी भाड़े और विदेशी बीमा के कारण समुचित समायोजन करने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के लिए कारखाना-गत कीमत का निर्धारण किया है जो,.... अमरीकी डालर/किग्रा. बैठती है।

इस प्रकार रिकार्डेड कीमतों के मामले में प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया पाटन मार्जिनरुपए प्रति किग्रा. या निर्यात कीमत का 93.19% बैठता है।

ईयू के अन्य निर्यातक

19. प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के ज्ञात निर्यातकों को जांच से संबंधित सूचना और उन पर टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, ऊपर उल्लिखित धारा के अनुसार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया प्राधिकारी ने भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल को भी लिखा। तथापि, यूरोपीय संघ के किसी अन्य निर्यातक ने सूचना के लिए प्राधिकारी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन किया है कि ईयू के निर्यातों के संबंध में जांच अवधि के लिए भारत औसत निर्यात कीमत सीमाशुल्क दैनिक सूची से एकत्र आंकड़ों के आधार पर निकाली जानी चाहिए। निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन हैंडलिंग इत्यादि के कारण किए गए समायोजनों पर विचार किया जाना चाहिए। जहाँ तक निर्यात कीमत का संबंध है घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान ईयू से कुल लदान तथा उन लदानों की वास्तविक सीआईएफ कीमतों को ध्यान में रखने के बाद निर्यात कीमत को औसत निर्यात कीमत के रूप में परिकलित किए जाने की मांग की है। प्राधिकारी ने स्वदेशी भाड़े, बीमा, विदेश भाड़े, विदेशी बीमा और मूल्यों के कारण समायोजन करने के पश्चात् घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के लिए कारखाना-गत कीमत का निर्धारण किया है जो,....यूएस डालर/किग्रा. बैठती है। समुद्री भाड़े (.....) प्रति टन समुद्री बीमा निर्यात कीमत की (.....) की दर पर, बिक्रियों की (.....) की दर पर कमीशन, लदान निर्यात कीमत की (.....) की दर पर और स्वदेशी भाड़ा (.....) की दर से निर्यात कीमत के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार समायोजन किए गए हैं।

प्राधिकारी ने ईयू के अन्य निर्यातकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार किया है।

इस प्रकार ईयू के पीएचपीजी बेस के असहयोगी/अन्य निर्यातकों के मामले में पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारारुपए प्रति किग्रा. अथवा 93.19% आंका गया है।

(ज) क्षति

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम-II में निम्नानुसार उल्लेख है :

क्षति का निर्धारण

- (i) विनिर्दिष्ट देशों से हुए आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करेगा कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा उत्पन्न होता है अथवा किसी उद्योग को स्थापित करने में बाधा आती है।
- (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति के खतरे घरेलू उद्योग की स्थापना में आने वाली वास्तविक बाधा पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर इसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों को परिणामी प्रभाव समेत सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का मूल्यांकन करेंगे।

21. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित क्षति के निर्धारण के सिद्धांतों में यह निर्धारित किया गया है कि :-

- (क) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा तथा समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल होगी।
- (ख) पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा काफी हद तक कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में उस वृद्धि को रोकना है जो कि अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

याचिकाकर्ता के विचार

22(i) इस याचिका को दायर करने से पहले घरेलू उद्योग को चीन, जपान और सिंगापुर से पीएचपीजी बेस के पाटन से नुकसान हो रहा था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित देशों से पीएचपीजी के आयातों के संबंध में जांच की थी और ऊपर उल्लिखित देशों पर अनन्तिम शुल्क लगाया गया है। इसी बीच सम्बद्ध देशों के निर्यातक भी भारतीय बाजार में पाटित सम्बद्ध वस्तु में इन देशों में शामिल हो गए हैं।

- (ii) संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है जो कि आयात संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट है ।
- (iii) प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से अधिक है ।
- (iv) याचिकाकर्ता एक नया प्रवेशकर्ता है । लेकिन संबद्ध देशों के निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योग कोई बाजार हिस्सा नहीं प्राप्त कर सके तथा यह आरंभिक स्थिति में ही समाप्त हो जाए । संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है जैसा कि उपरोक्त सारणी में उल्लेख किया गया है ।
- (v) जांच अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपनी वर्तमान क्षमता का केवल ***% उपयोग किया है ।
- (vi) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य में कमी आई है । निर्यात मूल्य में तेजी से आई कमी के कारण आयातक याचिकाकर्ताओं को अपना मूल्य आयातित मूल्य बराबर रखने के लिए बाध्य कर रहे हैं । तथापि, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को इतनी कम कीमत पर उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है जिससे उपान्तक कीमत भी वसूल नहीं हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को खो दिया है । चूंकि नए स्रोतों से आयात होना शुरू हो गया है इसलिए उद्योग विभिन्न स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी उचित मूल्य प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहा है ।
- (vii) चूंकि उद्योग अभी आरंभिक स्थिति में है और अनुचित व्यापार से इसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है अन्यथा इसमें कार्यरत श्रमिक अपना काम खो देंगे ।
- (viii) जहां तक लाभप्रदता का संबंध है, घरेलू उद्योग शुरू से ही घाटे में चल रहा है ।

(झ) प्राधिकारी द्वारा जांच

- 23 कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि पाटित आयातों के कारण भारत में समान वस्तुओं की कीमत की तुलना में कीमत में कोई उल्लेखनीय गिरावट आई है अथवा नहीं अथवा क्या इस प्रकार के आयातों से अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक गिरावट आई है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की है और यह पाया है

कि पाटित आयातों से कीमत में भारी कटौती हुई है। आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम पाया गया है। आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों पर पर्याप्त न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा था क्योंकि पाटित आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग अपना बिक्री मूल्य बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है।

24. भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, निवल बिक्री, प्राप्ति, लाभप्रदता इत्यादि जैसे अन्य संकेतों पर भी विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा जो निम्नलिखित हैं:-

(क) आयातों की मात्रा एवं निर्यात कीमत

संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा के संबंध में सूचना सीमाशुल्क दैनिक सूचियों से संकलित आंकड़ों पर आधारित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में 2000-01 की तुलना में ***% की वृद्धि हुई है इसके अलावा जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से औसत निर्यात कीमत में भी वर्ष 2000-01 की तुलना में गिरावट आई है।

यूरोपीय संघ से आयात

अवधि	मात्रा(किग्रा)	मूल्य लाख रूपए	औसत कीमत दर/ यूएस डालर मी	आयात का % हिस्सा
2000-01	24000	169.01	14907.85	2.38%
जांच अवधि (अप्रैल-दिसम्बर)	135000	749.49	11577.14	12.12%
जांच अवधि (2001-2002) वार्षिक	180	999.33	11577.14	12.12%

यूरोपीय संघ से माहवार आयात

अवधि 2001	मात्रा(किग्रा)	मूल्य (लाख रूपए में)	दर/यूएस डालर मी.टन
अप्रैल	शून्य	शून्य	शून्य
मई	शून्य	शून्य	शून्य
जून	शून्य	शून्य	शून्य

जुलाई	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर	45000	251.79	11816.90
अक्तूबर	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर	60,000	332.99	11502.15
दिसम्बर	30,000	154.71	11867.49

(ख) भारतीय उत्पादकों और संबद्ध देशों के आयातकों के बाजार हिस्सा में परिवर्तन-

प्राधिकारी यह पाते हैं कि मै0 डी ओ एल भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में नया प्रवेशकर्ता है और संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन बढ़ा दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योग को कोई बाजार हिस्सा न हो तथा उद्योग की स्थापना आरंभिक चरण में ही बाधित हो जाए ।

(ग) याधिकाकर्ता का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग

प्राधिकारी ने पाया कि याधिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता का केवल (***) का उपयोग किया है । देश में मांग को ध्यान में रखते हुए यह घरेलू उद्योग द्वारा जो उपयोग किया जा सकता था उससे काफी कम है ।

(घ) बाजार हिस्से की नगण्य वृद्धि

घरेलू उद्योग आरंभिक स्थिति में है, अतः पिछला रुझान उपलब्ध नहीं है लेकिन संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण देश में संबद्ध वस्तु की मांग अधिक होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा को बढ़ाने में असमर्थ है ।

(ङ.) बिक्री कीमत में कमी, कीमत न्यूनीकरण, कीमत में कटौती, कीमत में गिरावट अथवा कीमत

ह्रास

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संबद्ध वस्तु की मासिक बिक्री प्राप्ति का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है ।

अवधि	मात्रा बिक्री/किग्रा	निवल बिक्री प्राप्ति (रु०/किग्रा)
अप्रैल 2001	****	100
मई 2001	****	100
जून 2001	****	100
जुलाई 2001	****	89.47
अगस्त 2001	****	91.42
सितम्बर 2001	****	79.06
अक्तूबर 2001	****	75.61
नवम्बर	****	75.72
दिसम्बर	****	78.34

संकलित आकड़ों में अप्रैल 2001 को 100 माना गया है।

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान मासिक औसत बिक्री प्राप्ति अप्रैल 2001 के दौरान *** रु०/किग्रा से घटकर दिसम्बर 2001 के दौरान *** रु०/किग्रा रह गई है जिससे जांच अवधि के भीतर ही गिरावट प्रदर्शित होती है। यह मुख्यतः घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद निर्यातकों द्वारा औसत आयात कीमत में की गई कमी के कारण हुआ है।

(घ) गवाई गई संविदाओं अथवा कम होती हुई बिक्रियों का साक्ष्य

यह देखा गया है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात कीमत में तेजी से कमी किए जाने के कारण घरेलू उद्योग उस कीमत पर संविदाएं आदेश नहीं प्राप्त कर सका जिससे लगाई गई पूंजी पर उचित आय की प्राप्ति तो दूर उत्पादन लागत भी प्राप्त हो सके। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु को काफी घाटे पर ही बेच सका।

रोजगार

घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि उद्योग अपने आरंभिक चरण में है इसलिए अनुचित व्यापार प्रक्रिया से उसका बचाव करना महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक है अन्यथा कार्यरत कर्मचारियों को अपना रोजगार गवाना पड़ेगा।

(ज) लाभप्रदता

यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु की बिक्री निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों के बराबर कीमतों पर बेच सकता है जिससे उसे भारी घाटा हो सकता है।

25. वर्तमान याचिका मुख्यतः पाटित आयातों के प्रभाव से संबंधित है जोकि उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न कर रहा है। चूंकि याचिकाकर्ता अपने उत्पादन का निपटान भारतीय बाजार में ही करने की कोशिश कर रहा है तथा संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन के वाणिज्यीकरण को रोक रहे हैं, इसलिए आयात उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। यद्यपि नवस्थापित उद्योग अर्थात् मै० दौराला आरगैनैक्स लि० ने हाल ही में उत्पादन आरंभ किया है परन्तु उद्योग को अभी बाजार में अपना स्थान बनाना है। घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के संतोषजनक स्तर को पाने में तथा बाजार में अपना स्थान बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि आरंभिक चरण में ही घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर हुए आयातों द्वारा वास्तविक बाधा उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो रहा है।

(झ) कारणात्मक संबंध

26. यह निर्धारण करते समय कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति (वास्तविक/खतरा/ वास्तविक बाधा) पहुंची थी, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा:-

- 1) यूरोपीय संघ से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के पर्याप्त आयातों से घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत अलाभकारी स्तर तक घटाने के लिए विवश होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति पैदा हुई है।
- 2) यूरोपीय संघ से हुए आयातों से भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतें इस हद तक कम हो गईं कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की पूरी कीमत वसूलने और भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री से यथोचित लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गया।
- 3) इसलिए प्राधिकारी उपर्युक्त से यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कीमत पर हुए हैं। इसके अलावा भारत में आयात घरेलू उद्योग के क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा

है । याचिकाकर्ता को उसके क्षमता उपयोग के स्तर को बढ़ाने से भी रोका गया । ये मापदंड सामूहिक तथा संचयी रूप से यह इंगित करते हैं कि याचिकाकर्ता को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) भारतीय उद्योग का हित

27 पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है जोकि देश के सामान्य हित में है ।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास रुकेंगा और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से यूरोपीय संघ से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(ट) निष्कर्ष

28. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- (i) यूरोपीय संघ से भारत को डी(-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ii) भारतीय उद्योग को इससे वास्तविक क्षति हुई है और इसे आगे और क्षति होने का खतरा है;
- (iii) घरेलू उद्योग को उक्त क्षति के कारण डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस के विनिर्माण के लिए नए उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हो रही है ।

- (iv) प्राधिकारी अंतिम निर्धारण संबद्ध होने तक देशों से डी(-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस के सभी आयातों पर अनंतिम रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैरा ग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधिक के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनी की क्षति रहित कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है।
- (v) तदनुसार प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क शीर्ष 2942 के अंतर्गत आने वाले डी (-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस जिसे डी(-) अल्फा पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन, डी(-) अल्फा पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, डी(-) पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन, पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, डी(-) पी हाइड्रॉक्सी फिनाइल ग्लाइसीन नामों से भी जाना जाता है, के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाया जाए। नीचे उल्लिखित देशों के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाया जाने वाला पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम 3 में उल्लिखित राशि तथा प्रति किग्रा आयातों के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा:-

क.सं. 0.1	निर्यातक/देश 2	राशि अम.डालर प्रति किग्रा 3
1	डी एस एम डेरेंटिल एस ए स्पेन	21.38
2	रिक्कोडाटी, इटली	21.81
3	यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातक	21.81

- (vi) इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे।

(ठ) आगे की प्रक्रिया

29. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों से इन जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करेंगे और उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकारी द्वारा ज्ञात निर्यातकों, आयातकों, याचिकाकर्ता तथा अन्य हितबद्ध पक्षों के अलग से लिखा जा रहा है जो प्रारंभिक जांच परिणामों की तारीख से 40 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी अपने विचार इन जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
- (ग) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षों के मौखिक अनुरोध करने का अवसर प्रदान करेंगे जिन्हें बाद में लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (घ) प्राधिकारी आवश्यक समझी गई सीमा तक आगे सत्यापन करेंगे।
- (ङ.) प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की घोषणा करने से पहले आवश्यक तथ्यों को प्रकट करेंगे।

एल. बी. सप्तगुप्ति, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 5th June, 2002

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from the European Union.

No. 14/6/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE:

2. The procedure described below has been followed:

- (i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut, U.P. on behalf of the domestic industry, alleging dumping of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base also known as PHPG Base (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from European Union (hereinafter referred to as subject country / territory) ;
- (ii) The Authority notified the Delegation of European Commission in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 *supra*;
- (iii) The Authority issued a Public Notice dated 8th March 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base falling under Chapter heading 2942 of Schedule I of the Customs Tariff Act.
- (iv) The Authority forwarded copy of the said public notice to the known exporters, importers, industry associations and to the complainant and gave them an opportunity to make their views known in writing.

(v) According to sub-rule (3) of Rule 6 *supra*, the Authority provided a copy of the petition to all the known exporters of the European Union and Delegation of European Commission in India.

(vi) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from European Union:

❖ M/s. Recordati, Italy

❖ M/s DSM Deretil S.A. Spain.

Response has been received from both the exporters.

(vii) The Delegation of European Commission in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

(viii) The questionnaire was sent to the following known users/importers of subject goods:-

- M/s. Aurbindo Pharma Ltd, Hyderabad.
- M/s. Lupin Laboratories Ltd., Mumbai.
- M/s. Kopran Drugs Ltd., Raigad.
- M/s. Surya Pharmaceutical Ltd., Chandigarh.
- M/s. Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahamedabad.
- M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi.
- M/s. Tini Pharma Limited, Mumbai.

Response has been received from M/s Torrent Gujarat Biotech Ltd whose submissions are presented in the importer's response. Apart from this, no other users/importers has responded to the questionnaire.

(ix) Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also furnished;

(x) The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

(xi) **** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(xii) The investigation covered the period from 1st April 2001 to 31st December 2001;

(xiii) Copies of Initiation Notification were also sent to FICCI, CII, ASSOCHAM etc., for wider circulation.

B. PETITIONER'S VIEWS:

3. The petitioner, M/s Daurala Organics Ltd, has made the following points in their submissions: -

- (i) The product under consideration in the present petition is D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base). This product is also known as :
 - D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine
 - D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Base
 - D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine
 - Para Hydroxy Phenyl Glycine
 - D(-) P-Hydroxy Phenyl Glycine Base
 - D(-) P-Hydroxy Phenyl Glycine, etc.,
- (ii) The subject goods are imported into India, which is then converted in situ to PHPG Dane Salt (PHPGDS.) by the various importers/manufacturers and this compound is further used for the production of Amoxycillin and Cefadroxyl.
- (iii) The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act at sub heading number 294200 and 29420029 under 8 digit ITC code. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and the subject goods imported from subject country/ territory, which can have any impact of price usage, quality etc. Product produced by Daurala Organics Limited (DOL) and imported from subject country/ territory has similar characteristics and therefore, both should be treated as Like Articles.
- (iv) The petitioner represents the domestic industry, as they are the sole producer of the subject goods in India and therefore, fulfills the criteria as far as standing is concerned.
- (v) Prior to this petition, the domestic industry was suffering from dumping of PHPG base from China, PR and Singapore and the Designated Authority had already issued the Preliminary Findings on the subject material from these countries vide 51/1/2001-DGAD dated 31/12/2001 and the duty had already come into force with effect from 15th February, 2002 vide Ministry of Finance Notification No.18/2002-Customs dated 15th February 2002. In the meantime, producers/exporters in the subject country/ territory have also joined these countries in dumping subject material in the Indian market. Imports have

started coming in from EU at a very cheap price resulting dumping and these imports are causing injury to the domestic industry.

- (vi) Italy and Spain are members of European Union and there is no customs boundary in European Union. Thus, imposition of anti dumping duty cannot be effective without imposing duty against EU as a whole.
- (vii) The quantum of imports from the subject country is more than the de minimus limit.
- (viii) The petitioner has submitted that there is a substantial increase in exports from subject country/ territory in absolute terms, which is evident from the import data. The month wise import statistics show that exporters from Italy (EU) are reducing prices sharply after September 2001, which in their opinion cannot recover even their variable cost. The target of the exporter is just to kill the domestic industry at its nascent stage.
- (ix) The petitioner is a new entrant in this field and dumping from subject country/ territory is aimed to kill this industry at its very inception.
- (x) The present petition is against material retardation of the establishment of the industry. Since the petitioner is attempting to settle its commercial production in the Indian market and the imports from the subject country/ territory are preventing commercialization of the production by the domestic industry, the imports are causing material retardation to the establishment of the industry. Though, the "nascent industry" i.e. M/s DOL has recently started commercial production, the industry has yet to find its place in the market. Domestic Industry is unable to achieve a satisfactory level of capacity utilization and find its place in the market. Further, at nascent stage of production, it is being threatened with material injury by the exports from the subject country/ territory.
- (xi) The petitioner has claimed that the technology employed by it is comparable to the technology being used by the other producers in the world. Factors such as trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, the export performance or the productivity of the domestic industry have not caused injury to the domestic industry.
- (xii) Sharp increase in imports of subject goods at dumped prices has prevented the domestic industry not only to get its normal selling price but also prevented the domestic industry to remain in the market. The petitioners understand that European Union is having a significant freely disposable capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped imports to Indian market taking into account the limited availability of other export markets to absorb any additional exports.
- (xiii) The domestic industry has suffered huge losses at its nascent stage itself, in spite of a growing demand. Dumped imports from subject countries are the only reason causing material retardation of the establishment of the industry.

Further, at nascent stage of production, the Domestic Industry is being threatened with material injury by the exports at dumped prices from the subject country.

- (xiv) It is submitted that the Anti-dumping duty against the subject country be imposed from retrospective effect.
- (xv) The anti-dumping provisions under Section 9A(3) states as under in this regard:

"If the Central Government, in respect of the dumped article under inquiry, is of the opinion that –

There is a history of dumping which caused injury or that the importers was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury; and the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported articles dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied.

The Central Government may, by notification in the Official Gazette, levy Anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of Anti-dumping duty under-section (2) but not beyond ninety days from the date from the date of notification under the sub-section, and notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

It is evident from the above that the Central Government can impose Anti-Dumping Duty from retrospective effect in case:

- a. There is a history of dumping which caused injury;
- b. The importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury;
- c. The injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported article dumped and other circumstances are likely to serious undermine the remedial effect of the Anti-dumping duty liable to be levied.
- d. In the present case there is a clear history of dumping. Earlier the domestic industry has been injured from dumping of the subject material from the China and Singapore. The Designated Authority is conducting a detailed investigation and has already recommended preliminary findings and provisional anti-dumping duty has already been imposed by the Central Government. Now producers/exporter from the subject country/territory are dumping subject goods and are causing injury to the domestic industry. In this case the importers are well aware that the price at which the subject material is being exported from the subject country/territory is a dumped

price as the price is significantly below the reference price fixed by the Designated Authority in the earlier investigation (causing injury to the domestic industry).

- e. The injury is being caused by the producers/exporters from subject country/territory in a short period. There were little imports or nil imports from the subject country earlier. The dumping has commenced and got intensified very recently (more particularly from September, 2001). It is understood that the exporters have booked huge orders, which are under process of exportation.
- f. Most of the companies who are importing from the subject countries/territories are the companies who were earlier importing from China and Singapore.

C. EXPORTERS, IMPORTERS' AND USERS' VIEWS:

4. The Authority sent questionnaires to all the known exporters of subject country/ territory for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). The response filed by the exporters is as under:

a. M/s DSM Deretil, SA, Spain

It is seen that the exporter M/s DSM Deretil SA, Spain has not submitted any argument in their submission to the Designated Authority. However, they have responded to the questionnaire, which was sent to them along with the non-confidential copy of petition and they have submitted the data as per the different appendices mentioned in the questionnaire. They have submitted that

- i) DSM Deretil S.A. is an organization in the form of an autonomous society established and registered as per the laws of Spain by Colegio Nacional of Barcelona.
- ii) The exporter has represented that they receive no incentive from their government on export sales. They have added that they have no sales in the Spain or in the European union (Domestic market). However they have added that they have made sales to third countries.
- iii) They maintain that there is no difference between the production cost data supplied in the questionnaire and costs normally determined by them using their accounting system.
- iv) The exporter maintains that there is no specific evidence to material changes in the level of profits on sales made by DSM Deretil S.A. to India and other countries – due to reasons of quantities sold, conditions or terms of sale or of trade or such other factors.

b. **Recordati, Italy**

- i. M/s Recordati, Italy has represented that they produce the PHPG via Enzymatic route (petitioners route is chemical) since last 20 years and are reselling to Indian market at an average price in line with world market price. They have added that price level at which they sell their product in India comes after hard negotiations where quantity per order and international prices of Amoxy and Pen-G are taken into considerations.
- ii. They maintain that price erosion of both PHPG and Dane salt has been enhanced by several Chinese new producers of these commodities. They maintain that they don't have the resources to burn in an operation of dumping nor the intention to act against the interest of the petitioner.

IMPORTERS' AND USERS':

8. Only one user, namely, M/s. Torrent Gujarat Biotech Limited (TGBL) has responded to this petition. Their submissions are as follows:
 - a. There is no justification for fixing anti dumping duty on PHPG Base, imported from European Union considering the fact that the domestic industry maximum production capacity is only 300 MT as against an estimated demand of 2200-2500 MT/per annum.
 - b. The quality of the indigenous material available does not meet strictly to the specifications, which does not give them required yield and thus it affects the commercial viability of the finished product.
 - c. The landed prices of PHPG Base at the prevailing price of US \$ 11 per kg. Works out to be Rs.870.50 per kg. Including the duty, freight and the clearing charges etc. which is closer to the prevailing price of the local manufacturers M/s. Daurala Organics Limited. This indicates that the import price is parity with indigenous prices.
 - d. M/s DOL Ltd. is the only producer of this India and imposing of anti dumping duty on the subject material will become monopoly business which is against the MRTP Act.
- M/s TGBL has responded to the importers' questionnaire and has submitted information as in Annexure I to VII. They have also submitted annual report of their company for the year 2000-2001 and 1999-2000.

D. EXAMINATION AND FINDING BY AUTHORITY:

9. The submissions made by the petitioners, importers, exporters and other interested parties, to the extent filed before the Authority have been examined and considered while arriving at these findings and wherever appropriate have been dealt hereinafter.

E. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

10. The product under consideration in this investigation is PHPG Base. (Para Hydroxy Phenyl Glycine Base). The subject goods is imported in India which is then converted in situ to PHPG Dane Salt(PHPGDS) as PHPG cannot be used directly for the production of Amoxycillin etc. This conversion is done either at PHPG/PHPGDS manufacturers' end or at the users' ends i.e. producers of Amoxycillin etc. It is classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under sub heading 2942.00. As per ITC eight-digit classification PHPG is classified in "Others' categories' under chapter 29 i.e. 2942.0029. The present investigations are in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
11. Rule 2(d) of the anti dumping rule specifies that Like Article is an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation, or in absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.
12. The petitioner has claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject country. No dispute has been raised on the definition of the product under consideration and like article by any interested party in the investigation. The Authority notes that PHPG base produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those of the PHPG base imported from subject countries. In view of the above, the Authority holds that PHPG Base produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are Like Articles within the meaning of the rules for the purpose of injury determination.

De Minimus Limits

13. The petitioner has represented that the statistics shown in the DGCI&S data is not representative as other organic compounds under category "Others" are also cleared from the same heading 294200. Since the DGCI&S data does not give accurate import data for PHPG

Base, the petitioner has relied upon the data of secondary source i.e. from International business Information Services, Mumbai (IBIS). The data provided by the agency is based on Customs daily lists. The authority notes that PHPG Base is classified in "Others category" as per the Customs Tariff and hence the DGCI&S data may not be reliable under these circumstances. The IBIS import data for the last three years and month-wise data for the period of investigation indicate that the import from the subject countries during the POI is above the de minimus levels.

F. Domestic Industry

14. The petition has been filed by M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut, UP on behalf of domestic industry. The petitioner is the sole producer of PHPG in India. Accordingly, the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition on behalf of domestic industry in terms of Rule 5(3) of the Rules supra. The Authority also considers this petitioner as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) supra.

G. Examination of Normal Value, Export Prices and Dumping Margin

15. Under Section 9A(1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

M/s DSM Deretil, S.A. Spain.**Normal Value**

16. M/s DSM Deretil has replied that they have no domestic sales. They have given information in their response to their questionnaire in the prescribed format. As per Appendix -1 they have replied that they do not have any domestic sales and they have also added that they don't have any sales in the European Union for that product. As per Appendix -3 they have given an account of their sales to other countries and India, which is further split in month wise details of the sales. In the Appendix-4 & 6 they have given price structures and sales arrangements for sales to India and other countries. However they have given partial and incomplete information in the Appendix-7 of the questionnaire. Information with regards to the quantity and value for other products are not specified. As per appendix 8 and 10, they have not given complete information relating to financial and interest costs though in the annexure to these Appendices they have submitted some costs calculations with regards to the cost of the capital. They have also submitted their corporate balance sheets for the last three years.

The Authority notes that firm has submitted detailed information regarding the sales price structure for the exports to other countries and India though complete information relating to finance and interests costs have not been submitted and also the details regarding company's other product and their values are incomplete. The Authority also notes that exporter has not submitted transaction wise details in respect to third countries sales though they have submitted month wise details in respect to sales to third country which show that these sales are in ordinary course of trade. The Authority after examining the submissions of the exporter has come to a conclusion that by not giving all information as per the questionnaire, the authority is prevented to accept the submissions of the exporter in totality unless such a claim is supported by full information as required in the questionnaire. However since they have given adequate information regarding exports to other countries as per appendix-3 and 6, the authority accepts exporters submission for the normal value calculation strictly for the limited purpose of preliminary findings subject to further investigation and verification. The Authority has determined normal value as US\$ **** after taking account the sales price to third country (as a representative and appropriate third country) after making adjustments on account of inland freight, insurance, overseas freight, overseas insurance.

EXPORT PRICE:

17. The exporter has exported **** Kg. of PHPG to India for a total value of US\$****. They have given transaction wise details for export sales made to India and the Authority notes that these sales have been made under ordinary course of trade. Accordingly, the average export price of PHPG during the period of investigation works out to US\$**** per kg. The exporter has claimed adjustments on account of discount, inland freight, insurance, overseas freight,

181892/02-4

overseas insurance etc. to arrive at the ex-factory export price to India. However it is seen that the exporter has claimed less freight for exports to India as compared to exports to appropriate third country, which is nearer to EU. The authority has made adjustments taking the same freight as exports to Iran in the case of exports to India also and after considering the same the ex-factory price for export sales to India works out as US \$ ****/Kg. after making adjustments on account of inland freight, insurance, overseas freight, overseas insurance subject to further verification/investigation. The Authority has also taken into account commission at the rate of ****% of Export price as part of the adjustments to determining ex factory export price to India.

The dumping margin in case of M/s DSM Deretil S.A. from Spain is assessed by Authority at Rs **** per Kg or 6.68%% of the export price. ,

M/s Recordati, Italy :

18. M/s Recordatti has submitted their submissions in generalised form and they have commented only on the technology used by them and by the Petitioner. They have not submitted any information in the form and manner prescribed in Exporters Questionnaire. The Authority has, therefore, proceeded on the basis of Rule 6(8), i.e. best information available and has determined the normal value in respect of Recordati as per the information furnished by the domestic industry on the basis of constructed cost of production. As regards determination of export price the domestic industry has asked export price to be computed as average export price after taking into account total shipment from Italy during the POI and their actual CIF prices of their shipment. The Authority has assessed the ex-factory price for export sales to India as submitted by the domestic industry which works out as US \$ **** or Rs ****/Kg. after making appropriate adjustments on account of inland freight, insurance, overseas freight, Commission and overseas insurance.

Thus, the dumping margin in case Recordatti is assessed by Authority at Rs**** per Kg. or 93.19% of export price.

OTHER EXPORTERS FROM EU

19 .The Authority provided opportunity to the known exporters from EU to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Section cited above. The Authority wrote to the Delegation of EU in India also. However, no other exporters from EU have responded to the Authority's request for information. The petitioner has represented that weighted average export price should be arrived at based on the statistics compiled from Customs Daily Lists for the POI with regards to imports from EU. Adjustments on account of freight, marine insurance, commission, port handling etc., to arrive at net export price should be considered. As regards export price the domestic industry has asked export price to be computed as average export price after taking into account total shipment from EU during the POI and their actual CIF prices of their shipment. The Authority has assessed

the ex-factory price for export sales to India as submitted by the domestic industry which works out as US \$ ****/Kg or Rs ****/kg. after making adjustments on account of inland freight, insurance, overseas freight, overseas insurance and values as made in the case of M/s Recordati, Italy. The Authority has determined the Normal Value in respect of other exporters from EU as per the information furnished by the domestic industry on the basis of constructed cost of production.

Thus, the dumping margin in case of non-co-operative/other exporters of PHPG Base from EU is assessed by Authority at Rs **** per Kg. or 93.19%.

H. INJURY:

20. Rule 11 of Anti Dumping Rules reads as follows:

Determination of Injury:

(i) In the case of imports from specified countries, the Designated Authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry or materially retards the establishment of any industry in India;

(ii) The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules "

21. The principles for determination of injury set out in Annexure-II of the Anti-Dumping Rules lay down that:

a. Determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products

b. While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of Rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under-cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.

Views of the petitioners

22. (i) Prior to filing this petition, the domestic industry had been suffering from dumping of PHPG base from China PR and Singapore and the Designated Authority had conducted investigations in respect of imports of PHPG from above mentioned countries and provisional duties have been imposed on above mentioned countries. In the meantime exporters from subject countries have also joined these countries in dumping subject goods in the Indian market.

(ii) There has been a substantial increase in imports from subject countries in absolute terms, which is evident from the import data.

(iii) The quantum of imports from each of the subject country is more than the de-minimus limit.

(iv) The petitioner is a new entrant. But the exporters from subject countries are dumping the subject goods in India to make sure that domestic industry cannot get any market share and to kill it at its nascent stage itself. Market share of imports from subject countries has increased as described in the above table.

(v) During the period of Investigation the petitioner has achieved only 38% of its existing capacity.

(vi) The selling price of the domestic industry has declined during the period of investigation. Because of the sharp fall in the export price the importers are forcing the petitioners to match their price with the imported price. However the domestic industry is not in a position to provide the subject material at such a low price, which cannot recover even the marginal cost, resulting in a loss of customers. Therefore, the industry has not been able to realize a fair price even after imposition of anti-dumping duty on imports from various sources as imports have started from newer sources.

(vii) As the industry is at its nascent stage and protection from the unfair trade is vital and urgent otherwise the manpower deployed will lose its jobs.

(viii) As regards profitability, the domestic industry has been operating at a loss from the very beginning.

I. Examination by the Authority

23. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price under-cutting by the dumped imports. The landed value of imports

has been found to be significantly lower than the domestic industry's net sales realization. The imports were having significantly suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports.

24. For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority also considered such further indices having a bearing on the state of industry as capacity utilization, production, sales, net sales realization, profitability, etc. The Authority took into account various parameters indicating injury to the domestic industry, which are as follows:

(a) **Quantum of imports and export price**

The information with regard to the quantum of imports of the subject goods has been based on the statistics compiled from Customs Daily Lists. The Authority notes that there has been an increase of 562.5% in the volume of imports of the subject goods from the subject countries during the Period of Investigation over 2000-01. Further the average export price from the subject countries has also declined during the Period of Investigation against 2000-01.

Period	Qty(MT)	ValueRs Lakhs	Average price Rate/US\$MT	%share of Imports
2000-01	24	169.01	14907.85	2.38%
POI (April-December) 2001	135	749.49	11577.14	12.12%
POI (2001-02) Annualised	180	999.33	11577.14	12.12%

Imports from European Union

Month Wise Imports from European Union

Period 2001	Qty(Kg)	Value(Rs in Lakhs)	Rate/US\$MT
April	Nil	Nil	Nil
May	Nil	Nil	Nil

June	Nil	Nil	Nil
July	Nil	Nil	Nil
August	Nil	Nil	Nil
Sept	45000	251.79	11816.90
Oct	Nil	Nil	Nil
Nov	60,000	332.99	11502.15
December	30,000	164.71	11367.49

(b) Changes in market share held by Indian producers and imports from the subject countries:

The Authority observes that M/s DOL is the new entrant in manufacture of the subject goods in India and the exporters from subject countries have intensified dumping of the subject goods into India so as to ensure that domestic industry does not get any market share and also materially retard the establishment of the industry at its nascent stage itself.

(c) Production and Capacity utilisation of the petitioner:

The Authority observed that the petitioner has only achieved a utilization of ****% of its existing installed capacity during period of investigation. Keeping in view the demand in the country the same is far below than what could have been achieved by the Domestic Industry.

(d) Insignificant gain of market share:

Domestic industry is at nascent stage, hence no past trends are available but domestic industry is unable to increase its sales volume, in spite of huge demand of the subject goods in the country, because of dumped imports from subject countries.

(e) Reduction in selling price, price erosion, price undercutting, price suppression or price depression:

In order to analyze the effect of dumped imports on the selling price of the Domestic Industry an analysis of the monthly sales realisation of the subject goods has been made as under:

Period	Qty Sold/Kg	Net Sales Realization (Rs/Kg)
April-2001	****	100
May-2001	****	100
June-2001	****	100
July-2001	****	89.47
August-2001	****	91.42
Sepetember-2001	****	79.06
October 2001	****	75.61
November	****	75.72
December	****	78.34

Indexed Figures considering April 2001 as 100

The table above indicates that the monthly average sales realisation during the Period of Investigation has declined from **** Rs/ Kg. during April 2001 to **** Rs/ Kg. during December 2001 showing a decrease within the Period of investigation itself. This is mainly due to decrease in the average import price by the exporters after the starting of the commercial production by the Domestic Industry.

(f) Evidence of lost contracts or declining sales:

It has been observed that because of the sharp decrease in the export prices by the exporters, the Domestic Industry could not gain contracts/orders at the prices which could recover the cost of production leave aside a fair return on capital employed. The petitioner could sell the subject goods at substantial losses only.

(g) Employment:

The domestic industry has submitted that as the industry is at its nascent stage, protection from unfair trade practice is vital and urgent otherwise the manpower deployed will loose their jobs.

(h) Profitability:

It has been observed that the Domestic Industry could sell the subject goods at prices so as to match the same being offered by the exporters resulting in huge losses.

25. The present petition is basically regarding impact of dumped imports causing material retardation of the establishment of the industry. Since the petitioner is attempting to settle its production in the Indian market and the imports from the subject countries are preventing commercialisation of the production by the domestic industry, the imports are causing material retardation to the establishment of the industry. Though, at the "nascent industry" i.e. M/s Daurala Organics Ltd. has recently started production, the industry is yet to find its place in the market. Domestic Industry is unable to achieve a satisfactory level of capacity utilisation and to find its place in the market, because, at the nascent stage itself the domestic industries is being threatened with material retardation, by imports at dumped prices from the subject countries.

J. Causal Link

26. In determining whether injury (material/threat/material retardation) to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

(i) Substantial imports of subject goods from European Union at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-remunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.

(ii) The imports from European Union suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

(iii) The Authority, therefore, notes from the above that the imports from the subject countries have been at a price below the selling price of the domestic industry. Further, the imports into India have been at a price lower than the non-injurious price for the domestic industry. As a consequence thereof the domestic industry is suffering financial losses. The petitioner was also prevented from increasing the level of capacity utilisation. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST:

27. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from European Union in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

L. CONCLUSIONS:

28. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

(i) D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base has been exported to India from European Union below its normal value;

(ii) The Indian industry has suffered material injury and facing threat of further injury.

(iii) The Domestic Industry, on account of the injury being suffered, is facing material retardation in the establishment of new industry to manufacture D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base.

(iv). The Authority considers it necessary to impose an anti dumping duty provisionally, pending final determination, on all imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is proposed to be compared with the Non Injurious Price of the petitioner company determined for the period of investigation.

(v). Accordingly, the Authority recommends that the provisional anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base also known as D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine, D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine, Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, Para Hydroxy Phenyl Glycine, D (-) P – Hydroxy Phenyl Glycine Base, D (-) P – Hydroxy Phenyl Glycine falling under Custom Heading 2942 originating in or exported from European Union pending final determination. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column 3 of the following table and the landed value of

imports per Kg. to be imposed from the date of Notification to be issued in this regard by the Central Govt. on all the imports of subject goods falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from the countries mentioned below: -

S. No. 1.	Exporter/Country 2.	Amount(US\$ Per Kg.) 3.
1.	<u>DSM Deretil S.A., Spain</u>	21.38
2.	<u>Recordati, Italy</u>	21.81
3.	Other exporters from European Union	21.81

(vi). Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

M. FURTHER PROCEDURE:

29. The following procedure would be followed subsequent to notifying the preliminary findings: -

(a) The Authority invites comments on these findings from all interested parties and the same would be considered in the final findings:

(b) Exporters, importers, petitioner and other interested parties known to be concerned are being addressed separately by the Authority, who may make known their views, within forty days from the date of preliminary findings. Any other interested party may also make known its views within forty days from the date of publication of these findings;

(c) The Authority would provide opportunity to all the interested parties for making oral submissions, which have to be rendered thereafter in writing;

(d) The Authority would conduct further verification to the extent deemed necessary;

(e) The Authority would disclose essential facts before announcing final findings.

L V SAPTHARISHI, Designated Authority